* 19th Year
* Issue: 295
* 07.03.2026 (SATURDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

ओड़िशा में सीआईएसएफ स्थापना दिवस पर गरजे अमित शाह, बोले-३१ मार्च तक देश से नक्सलवाद का होगा खात्मा

भुवनेश्वर ०६/०३ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दोहराया कि सुरक्षा बल 31 मार्च, 2026 तक देश से नज़्सलवाद को जड़ से खत्म करने के अपने संकल्प को पूरा करेंगे। कटक में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 57वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए अमित शाह ने नज़्सलवाद के उन्मूलन में सीआईएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार 31 मार्च, 2026 तक देश को नज़्सलवाद से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सीआईएसएफ ने इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे ओडिशा हो, छज़्ीसगढ़ हो या तेलंगाना, सीआईएसएफ ने नज़्सलवाद के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शाह ने साफ तौर पर कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च, 2026 तक यह देश नज़्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। हमारे सुरक्षा बल तिरुपति से पशुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने और अपना वर्चस्व स्थापित करने का सपना देखने वालों को पूरी तरह से पराजित करेंगे। अमित शाह ने देश के लिए सीआईएसएफ कर्मियों के वीरता और आत्मबलिदान की सराहना करते हुए उनकी सेवा के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि 56 वर्षों में, सीआईएसएफ ने न केवल अपने मूल उद्देश्य को पूरा किया है, बल्कि हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को रूपांतरित भी किया है। वीरता और बलिदान भारत के गौरवशाली इतिहास की पहचान हैं।

इन गुणों को समर्पण के साथ जोड़ते हुए और आधुनिक हथियारों से लैस होकर, सीआईएसएफ ने हर तरह की चुनौतियों का सामना करने का साहस दिखाया है। मैं बल के सभी कर्मियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

शाह ओडिशा के कटक जिले के मुंडाली स्थित खारवेला क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री का भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर मुज़्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने स्वागत किया, जब वे विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राज्य पहुंचे थे। अमित शाह भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के परिसर में स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) का भूमि पूजन भी करेंगे। शाह भुवनेश्वर में %नई न्याय संहिता% पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और एक मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाएंगे।

संसद में महामुकाबले की तैयारी? भाजपा-कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया तीन-पंक्ति का व्हिप

नयी दिल्ली ०६/०३ (संवाददाता): सज़ाधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने शुक्रवार को अपने लोकसभा सांसदों को बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान 9 से 11 मार्च तक सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तीन-पंक्ति का व्हिप जारी किया। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें मुज़्य रूप से आवश्यक विधायी और अन्य कार्यवाहियों पर चर्चा होने की उज़्मीद है। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त हुआ, जिसमें भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के संस्मरण पर राजनीतिक बहसें हुईं, जिनके प्रकाशन की स्थिति संसद के बाहर भी विवाद का विषय बनी रही। संसद का बजट सत्र, जो 28 जनवरी को राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ, 65 दिनों में 30 बैठकों का है और 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। अवकाश के दौरान स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान अनुरोधों की जांच करेंगी। सत्र का पहला भाग मुज़्य रूप से 2026-27 के बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समर्पित था। इंडिया ज़्लॉक ने सत्र के प्रारंभ तक एमजीएनआरईजीए को विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम से बदलने और मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चर्चा की। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के दौरान, विपक्षी दलों ने एमजीएनआरईजीए को समाप्त करने के विरोध में गरिमापूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखा। 1 फरवरी को विज़ मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार नौवां बजट था।

विज़ मंत्री ने राजकोषीय उज़रदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के तहत सदन के समक्ष दो वक्तव्य भी प्रस्तुत किए। इनमें मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य और मैक्रो-आर्थिक ढांचा वक्तव्य शामिल हैं।

बिहार की सियासत में नया अध्याय: नीतीश की विरासत संभालेंगे बेटे निशांत, जदयू में होगी एंट्री

पटना ०६/०३ (संवाददाता): बिहार के मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शनिवार को जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल होंगे और संभवत: उन्हें बिहार का उपमुज़्यमंत्री बनाया जाएगा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद सामने आया है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लगातार मांग की है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। शुक्रवार की बैठक में यह मांग एक बार फिर उठाई गई, जिसमें पार्टी नेताओं ने कहा कि निशांत अपने पिता की जगह लेने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होंगे।

जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि निशांत कुमार (मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे) कल जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल होंगे। निशांत कुमार ने पूरे राज्य का दौरा करने का फैसला किया है। नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वे विधायकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकार गठन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। नीतीश के मुज़्यमंत्री बनने के साथ ही बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अपना मुज़्यमंत्री होगा। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि इसी के साथ निशांत को राज्य का उपमुज़्यमंत्री बनाया जाएगा।

बिहार की मंत्री लेशी सिंह ने शुक्रवार को आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए बिहार के मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार के नामांकन दाखिल करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनात्मक प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुमार ने 20 वर्षों से अधिक समय तक राज्य का नेतृत्व किया है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता उनके इस निर्णय से असहज हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि नीतीश कुमार 20 वर्षों से अधिक समय से बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने बिहार में सभी कार्य किए हैं, सुशासन स्थापित किया है, कानून का शासन स्थापित किया है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है; यह स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता उनके इस निर्णय से असहज महसूस कर रहे हैं।

सिंह ने आगे कहा कि शाम 5 बजे एक बैठक होगी। बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसकी जानकारी दी जाएगी।

असम में वायुसेना का सुखोई दुर्घटनाग्रस्त, दो पायलट शहीद

गुवाहाटी ०६/०३ (संवाददाता): भारतीय वायुसेना (ढ्ढस्न) ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि असम के कार्बी आंगलोंग जिले में एक सुखोई फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो जांबाज पायलट शहीद हो गए हैं। यह हादसा गुरुवार शाम उस समय हुआ जब विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि असम के कार्बी आंगलोंग जिले में एक सुखोई स्ह्व-30स्ब्यद्ब फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो जांबाज पायलट शहीद हो गए हैं। यह हादसा गुरुवार शाम उस समय हुआ जब विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था। एक बयान में, ढ्ढस्न ने पायलटों की पहचान स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ़्लाइट लेफ़्टिनेंट पुरवेश दुरगकर के तौर पर की। आज सुबह, ढ्ढस्न ने कन्फ़र्म किया था कि फ़ाइटर जेट जोरहाट एयरबेस से लगभग 60 द्मद्व दूर कार्बी आंगलोंग के एक पहाड़ी इलाके में गिरा। ढ्ढस्न ने एक बयान में कहा, जो एक ट्रेनिंग मिशन पर था, जोरहाट से लगभग 60 द्मद्व दूर कार्बी आंगलोंग के इलाके में क्रैश हो गया। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। गुरुवार को जोरहार से सुखोई के उड़ान भरने के बाद, प्लेन का ग्राउंड कंट्रोल से आखिरी कज़्युनिकेशन शाम 7.42 बजे हुआ था। 2000 के दशक की शुरुआत में एयर फ़ोर्स में शामिल किया गया सुखोई स्ह्व-30 स्ब्यद्ब सबसे काबिल फ्रंटलाइन कॉज़्बैट एयरक्राज़्ट में से एक माना जाता है।

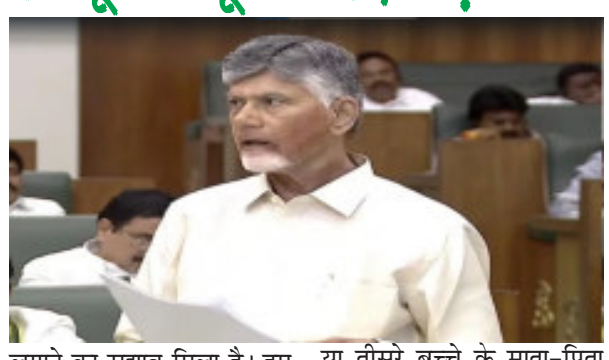

आंध्र प्रदेश में तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे 25,000, एन चंद्रबाबू नायडू ने दिए बड़े संकेत

०६/०३ (संवाददाता): आंध्र प्रदेश के मुज़्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू में राज्य की संज़्या बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जो भी माता-पिता दूसरे बच्चा पैदा करेंगे, सरकार उन्हें 25000 रुपये का इंसेंटिव (आर्थिक मदद) देने पर विचार कर रही है। एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के सीएम की बागडोर संभालने के बाद कहा था कि दक्षिण की आबादी घट रही है। ऐसे में हमें ज्यादा बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुज़्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार गिरती जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए यह बयान दिया था। अब नायडू ने कहा कि सरकार दूसरा बच्चा करने वाले जोड़ों को आर्थिक मदद देने की दिशा में सोच रही है। मुज़्यमंत्री ने कहा कि हमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव मिला है। हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले 90 दिनों में 13 साल से कम उम्र के बच्चों की इस तक कोई पहुंच न हो। इस बात पर चर्चा चल रही है कि यह आयु सीमा 13 साल होनी चाहिए या 16 साल। अगर सभी सहमत होते हैं, तो हम फैसला लेंगे। इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुज़्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार एक नई जनसंज़्या प्रबंधन नीति पर विचार कर रही है जिसमें परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विज़ीय प्रोत्साहन शामिल हैं। उन्होंने घोषणा की कि दूसरे या तीसरे बच्चे के माता-पिता को प्रसव के समय 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। आंध्र प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए, मुज़्यमंत्री नायडू ने राज्य की प्रस्तावित जनसंज़्या प्रबंधन नीति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 58 प्रतिशत परिवारों में केवल एक बच्चा है, लगभग 2.17 लाख परिवारों में दो बच्चे हैं और लगभग 62 लाख परिवारों में तीन या अधिक बच्चे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग तीन लाख परिवारों में दो के बजाय केवल एक बच्चा है, जबकि अन्य तीन लाख परिवारों में दो से अधिक बच्चे हैं।

चुनाव से पहले ममता का विरोध, बोलीं-बंगाल के वोटरों को उनका हक दिलाकर रहूंगी

कोलकाता ०६/०३ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया और कहा कि वह भाजपा-चुनाव आयोग की बंगाल के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश का पर्दाफाश करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा-चुनाव आयोग की बंगाल के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश का पर्दाफाश करूंगी। मैं चुनाव आयोग द्वारा मृत घोषित किए गए मतदाताओं को कोलकाता में पेश करूंगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले, मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में एसआईआर के बाद मतदाता सूचियों में कथित मनमानी तरीके से नाम हटाए जाने के विरोध में धरना शुरू किया।

यह विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ के राज्य दौरे से ठीक दो दिन पहले हो रहा है। मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले इस धरने की घोषणा टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को की। उन्होंने चुनाव आयोग पर विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लाखों वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने वाली राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। यह विरोध प्रदर्शन सज़ारूढ़ पार्टी द्वारा राजनीतिक तनाव बढ़ाने का एक बड़ा संकेत है, जो चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के बाद की मतदाता सूची प्रकाशित करने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। एसआईआर ने राज्य के मतदाताओं की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

28 फरवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवंबर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगभग 8.3 प्रतिशत मतदाताओं यानी 63.66 लाख नाम हटाए जा चुके हैं, जिससे मतदाता आधार लगभग 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ से थोड़ा अधिक रह गया है।

दिल्ली विस के फांसी घर पर घमासान, केजरीवाल ने भाजपा को दी चुनौती-सबूत कहां है?

नयी दिल्ली ०६/०३ (संवाददाता): पूर्व मुज़्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को %फांसी घर% मामले के सिलसिले में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश हुए। प्रद्युमन सिंह राजपूत की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में केजरीवाल ने विधानसभा परिसर में स्थित एक शाज़्ट को %फांसी घर% घोषित करने और उसे आम जनता के लिए खोलने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। विशेषाधिकार समिति में विधायक सूर्य प्रकाश खत्री, अभय कुमार वर्मा, अजय कुमार महावर, सतीश उपाध्याय, नीरज बसोया, रवि कांत, राम सिंह नेताजी और सुरेंद्र कुमार भी शामिल हैं। यह मामला मूल रूप से दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा उठाया गया था और इसमें दिल्ली विधानसभा परिसर के भीतर 9 अगस्त, 2022 को उद्घाटन किए गए %फांसी घर% की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा परिसर एक ऐतिहासिक इमारत है। यह इमारत 1912 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनी थी, जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 2022 में, तत्कालीन अध्यक्ष राम निवास गोयल के प्रयासों से पता चला कि इस इमारत के एक कोने में फांसी का तज़्ता था। वहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी।उन्होंने आगे कहा कि तत्कालीन अध्यक्ष ने मुज़्यमंत्री रहते हुए मुझे बुलाया और कहा कि हमें इसे पर्यटकों के लिए खोल देना चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सकें। मैंने इसे खोला और इसका उद्घाटन किया। अब, जब से उनकी सरकार सज़ा में आई है, वे यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह फांसी का तज़्ता नहीं, बल्कि एक टिफिन रूम था।

मेरा मानना है कि स्वतंत्रता सेनानियों का इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। मुझे आज विधानसभा में बुलाया गया और मुझसे यह साबित करने को कहा गया कि यह फांसी का तज़्ता था। मैंने जवाब दिया कि तत्कालीन अध्यक्ष ने गहन जांच के बाद ऐसा साबित किया था। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि उनके पास ज़्या सबूत है कि यह एक टिफिन रूम था। उनके पास कोई सबूत नहीं है... जब से भाजपा सरकार सज़ा में आई है, दिल्ली की हालत बेहद खराब है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली के लोग रो रहे हैं। उन्हें फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार याद आ रही है। दिल्ली में हर जगह कूड़ा-कचरा फैला है। प्रदूषण भयानक है। सड़कें टूटी-फूटी हैं। मोहल्ले के ज़्लीनिक बंद हो रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं... अगर उनकी किसी कमेटी ने मुझसे पूछा होता, केजरीवाल जी, मुझे बताइए सीवर कैसे ठीक करें, सड़कें कैसे ठीक करें। तो मुझे खुशी होती। मैं अपना अनुभव साझा करता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार सज़ा में है। मैं बस इतना चाहता हूं कि दिल्ली में सुधार हो। लेकिन वे दिल्ली चलाना ही नहीं चाहते।

विविध समाचार

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित, 958 का चयन, राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री टॉपर

नयी दिल्ली ०६/०३ (संवाददाता): आखिरकार लाखों अज़्यर्थियों के लंबे इंतजार के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने शुक्रवार को परिणाम घोषित किया, जिसके बाद अब अज़्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट सूची देख सकते हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार इस वर्ष कुल 958 अज़्यर्थियों को विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। बता दें कि अंतिम परिणाम अज़्यर्थियों के लिखित मुज़्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण यानी साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया गया है।गौरतलब है कि इस बार परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया है। वह मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले बताए जाते हैं और पेशे से चिकित्सक हैं। उनके शीर्ष स्थान प्राप्त करने की खबर सामने आने के बाद उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।

आयोग की ओर से जारी

मेरिट सूची में सामान्य वर्ग से 317, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 104, अन्य पिछड़ा वर्ग से 306, अनुसूचित जाति से 158 और अनुसूचित जनजाति से 73 अज़्यर्थियों को चयनित किया गया है। इस तरह कुल 958 उज़्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं के लिए अनुशंसित किया गया है।

इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत भी कुछ अज़्यर्थियों का चयन किया गया है। उपलज़्ध आंकड़ों के अनुसार पहली दिव्यांग श्रेणी से 10, दूसरी श्रेणी से 14, तीसरी श्रेणी से 9 और पाँचवीं श्रेणी से 9 अज़्यर्थियों को अवसर मिला है।बता दें कि आयोग ने एक आरक्षित सूची भी जारी की है। मौजूद जानकारी के अनुसार आरक्षित सूची में कुल 258 उज़्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें सामान्य वर्ग के 129, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 26, अन्य पिछड़ा वर्ग के 86, अनुसूचित जाति के 8 और अनुसूचित जनजाति के 6 अज़्यर्थी शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी के भी कुछ उज़्मीदवार आरक्षित सूची में रखे गए हैं।अगर सेवा-वार रिक्तियों की बात करें तो इस बार सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कुल 180 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं भारतीय पुलिस सेवा के लिए 150 और भारतीय विदेश सेवा के लिए 55 पद तय किए गए हैं।

इसके अलावा केंद्र सरकार की समूह 'क' सेवाओं के लिए 507 और समूह 'ख' सेवाओं के लिए 195 पद निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर विभिन्न सेवाओं में एक हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां किए जाने की योजना बताई जा रही है।गौरतलब है कि सिविल सेवा परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर साल देशभर से लाखों उज़्मीदवार इसमें शामिल होते हैं, लेकिन तीन चरणों प्रारंभिक परीक्षा, मुज़्य परीक्षा और साक्षात्कार को पार करने के बाद ही बहुत कम अज़्यर्थी अंतिम मेरिट सूची तक पहुंच पाते हैं।इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय व्यापार सेवा समेत कई अन्य केंद्रीय सेवाओं में भी नियुक्तियां की जाती हैं। चयनित अज़्यर्थियों को उनकी रैंक और सेवा वरीयता के आधार पर अलग-अलग सेवाओं में तैनाती दी जाती है।

बता दें कि अज़्यर्थी अपना परिणाम देखने के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलज़्ध सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम से जुड़े लिंक पर जाकर सूची देख सकते हैं। इसके बाद खुलने वाली पीडीएफ सूची में अपना नाम या अनुक्रमांक खोजकर परिणाम देखा जा सकता है।

आयोग की ओर से यह भी बताया गया है कि सभी उज़्मीदवारों की विस्तृत अंकसूची परिणाम घोषित होने के लगभग 15 दिन बाद वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यह अंकसूची लगभग 30 दिनों तक वेबसाइट पर उपलज़्ध रहेगी, जिसके दौरान अज़्यर्थी इसे डाउनलोड कर सकेंगे।इस तरह एक बार फिर सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम देश के हजारों युवाओं के लिए नई उज़्मीद और प्रेरणा लेकर आया है। चयनित उज़्मीदवार अब देश की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं।

नीतीश के फैसले से जदयू में बगावत, रोते हुए समर्थक बोले- हम आपको जाने नहीं देंगे

पटना ०६/०३ (संवाददाता): बिहार के मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के फैसले से राज्य में नए मुज़्यमंत्री का रास्ता खुल गया है, जिससे जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकर्ता और समर्थक हैरान हैं। पटना में मुज़्यमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे जेडीयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार ने मुज़्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला कर लिया है।एक जेडीयू कार्यकर्ता ने नीतीश कुमार की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हो सकता है कि उनका अकाउंट हैक हो गया हो। एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि अगर मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार अपना फैसला नहीं बदलते हैं तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे।

एक जदयू कार्यकर्ता ने कहा कि ये दुखद है। जो नीतीश कुमार छात्र आंदोलन से लेकर आज तक बिहार की जनता की सेवा करते रहे... बिहार की जनता उन्हें अपना परिवार मानती है। नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई यहां मुज़्यमंत्री नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुज़्यमंत्री बने रहें। जदयू नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा कि हम लोग रोएं नहीं तो ज़्या करें? लाठी खाकर, लात खाकर हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुज़्यमंत्री बनाया, 2025 में हमने नीतीश कुमार के नाम पर घर-घर जाकर वोट मांगें। आज नीतीश कुमार मुज़्यमंत्री नहीं रहे तो बिहार के लोग कहां जाएंगे? आज ही आप चुनाव करवा लें और जिसे मुज़्यमंत्री बनाना है बना लें... कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि निशांत(नीतीश कुमार के बेटे) को राज्यसभा भेजें।

उन्होंने कहा कि यदि किसी को मुज़्यमंत्री बदलने की इच्छा है, उन्हें लगता है कि उनमें नेतृत्व बदलने की ताकत है, उनके चेहरे में इतनी ताकत है तो वे चुनाव करवा लें और बहुमत ले लें हम कुछ नहीं कहेंगे... हम लोग यहां पर रहेंगे और उन्हें(नीतीश कुमार) नामांकन भरने के लिए नहीं जाने देंगे। निशांत कुमार का नामांकन होगा, नीतीश कुमार को हम जाने नहीं देंगे। एक अन्य समर्थक ने कहा कि नीतीश कुमार जनता के जनादेश का अपमान नहीं कर सकते। उन पर एक बड़ी साजिश के तहत भारी दबाव है। एक अन्य समर्थक नीतीश कुमार के फैसले से बेहद दुखी दिखे और उन्होंने उनसे मुज़्यमंत्री बने रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह दिल तोड़ने वाला है। नीतीश कुमार छात्र आंदोलन से लेकर आज तक बिहार की जनता की सेवा करते आए हैं... बिहार की जनता उन्हें अपना परिवार मानती है। नीतीश कुमार के अलावा कोई और यहां मुज़्यमंत्री नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुज़्यमंत्री बने रहें।

सेना के नंबर 2 बनेंगे जनरल धीरज सेठ, संभालेंगे उप सेना प्रमुख का अहम पदभार

नयी दिल्ली ०६/०३ (संवाददाता): लेज़्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो वर्तमान में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ हैं, 1 अप्रैल, 2026 से नई दिल्ली स्थित सेना मुज़्यालय में उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने वाले हैं।

यह नियुक्ति भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा है, जिसमें कई प्रमुख परिचालन कमानों के उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं। उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी नई भूमिका में, लेज़्टिनेंट जनरल सेठ भारतीय सेना के सर्वोच्च पदों में से एक का आधिपत्य करेंगे, जो सेना प्रमुख के बाद दूसरे स्थान पर है।

इस पद में महत्वपूर्ण जिज़्मेदारियां शामिल हैं, जिनमें सेना की परिचालन तत्परता, आधुनिकीकरण के प्रयास, रणनीतिक योजना और देश भर में विभिन्न सेना कमानों और इकाइयों के समन्वय की देखरेख करना शामिल है। लेज़्टिनेंट जनरल सेठ पुणे स्थित दक्षिणी कमान का नेतृत्व कर रहे हैं, जो भारतीय सेना की सबसे व्यापक भौगोलिक कमानों में से एक है और प्रायद्वीपीय भारत में सैन्य अभियानों और बुनियादी ढांचे के लिए जिज़्मेदार है। उनके नेतृत्व में, दक्षिणी कमान ने रणनीतिक भंडार बनाए रखने, बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अज़्यास आयोजित करने और आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों में सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में कमान के भीतर परिचालन तत्परता और प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।

सेना मुज़्यालय में उनका स्थानांतरण उनके सैन्य करियर

में एक महत्वपूर्ण उपलज़्धि है, ज़्योंकि वे भारतीय सेना के केंद्रीय निर्णय लेने वाले स्तर पर अपने साथ क्षेत्र कमान का व्यापक अनुभव लेकर आ रहे हैं।

उप-प्रमुख की भूमिका सेना की दैनिक रणनीतिक गतिविधियों के प्रबंधन में अभिन्न होती है, जिसमें नीति क्रियान्वयन, क्षमता संवर्धन और दीर्घकालिक परिचालन योजना की देखरेख शामिल है। उप-प्रमुख की जिज़्मेदारियों में रक्षा मंत्रालय, अन्य सैन्य शाखाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से जुड़े विभिन्न सरकारी निकायों के साथ समन्वय करना भी शामिल है। इस भूमिका के लिए एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जिसके पास सैन्य नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं में गहन परिचालन अंतर्दृष्टि और अनुभव हो।

लेज़्टिनेंट जनरल सेठ की उप-प्रमुख के रूप में नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारतीय सेना आधुनिकीकरण, तकनीकी एकीकरण और अपनी सक्रिय सीमाओं पर मजबूत परिचालन तत्परता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सेना को पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा और चीन के साथ उज़री और पूर्वी सीमाओं पर महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उच्चतम स्तर पर रणनीतिक नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

लेज़्टिनेंट जनरल सेठ जैसे अनुभवी नेता की नियुक्ति से सेना की रणनीतिक योजना और शीर्ष स्तर पर परिचालन समन्वय में मजबूती आने की उज़्मीद है। एक प्रमुख परिचालन इकाई का नेतृत्व करने का उनका अनुभव सेना मुज़्यालय को बहुमूल्य दृष्टिकोण प्रदान करेगा, ज़्योंकि सेना उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूलन कर रही है।

नेतृत्व परिवर्तन भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्रीय कमानों और सेना मुज़्यालय में महत्वपूर्ण स्टाफ पदों के बीच बारी-बारी से नियुक्त करने की परंपरा को भी दर्शाता है। इस तरह की नियुक्तियों से यह सुनिश्चित होता है कि सेना के शीर्ष नेतृत्व में परिचालन विशेषज्ञता और रणनीतिक अंतर्दृष्टि का संतुलन बना रहे।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच राजनाथ सिंह का आत्मनिर्भर मंत्र

नयी दिल्ली ०६/०३ (संवाददाता): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड और एक निजी मीडिया संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रक्षा और समुद्री संवाद सागर संकल्प - भारत की समुद्री शान की वापसी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अनिश्चितता के इस वर्तमान युग में प्रासंगिक और तैयार रहने का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान वैश्विक स्थिति के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन, नए समीकरणों का निर्माण और समुद्री गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हुई है, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकार के संकल्प की पुष्टि करता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पुराने विचार, पुरानी वैश्विक व्यवस्था और पुरानी धारणाएं तेजी से बदल रही हैं। ये वे अनिश्चितताएं हैं जिन्हें हमें समझना होगा। मध्य पूर्व की

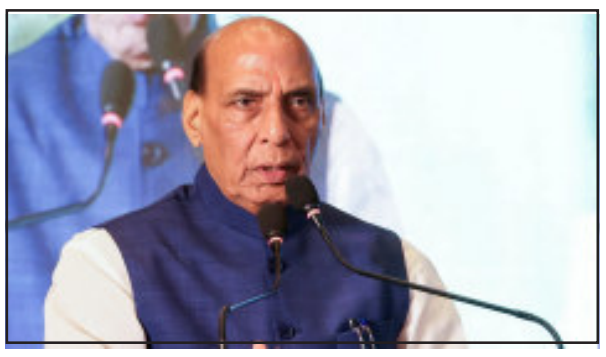

वर्तमान स्थिति इसका एक प्रमुख उदाहरण है। वहां जो हो रहा है वह काफी असामान्य है। मध्य पूर्व या हमारे पड़ोस में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में ठोस टिप्पणी करना मुश्किल है।

उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य या पूरा फारस की खाड़ी क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जब इस क्षेत्र में अशांति होती है, तो इसका सीधा असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ता है।

इसके अलावा, हम अन्य क्षेत्रों में भी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान देख रहे हैं। इन अनिश्चितताओं का अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वैश्विक परिदृश्य एक असामान्य स्थिति है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह असामान्य स्थिति अब सामान्य मानी जाने लगी है।

राजनाथ सिंह ने तकनीकी गतिशीलता को आज की दुनिया का एक और महत्वपूर्ण तत्व बताते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव ला रही है, और यह रक्षा क्षेत्र में और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि रक्षा क्षेत्र में उच्च स्तरीय और सटीक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है, और सरकार उभरती और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखती है।

खाड़ी देशों में फंसे 12 हजार भारतीयों ने मोदी सरकार से लगाई मदद की गुहार, विदेश मंत्रालय आया एज़्शन में

नयी दिल्ली ०६/०३ (संवाददाता): पश्चिम एशिया में भड़की अमेरिका-इजराइल-ईरान जंग के सातवें दिन हालात और भयावह हो गए हैं। लगातार हो रहे हमलों और बंद होते हवाई रास्तों के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की बेचैनी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्टों के अनुसार करीब 12 हजार भारतीय नागरिकों ने अपने वतन लौटने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है और क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावासों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा संकट संयुक्त अरब अमीरात में दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के कारण वहां का हवाई क्षेत्र लगभग बंद है और सामान्य उड़ान सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ी हैं। इस कारण हजारों भारतीय यात्री वहां फंस गए हैं और उनके सामने घर वापसी का रास्ता लगभग बंद हो गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, इन फंसे हुए भारतीयों में बड़ी संज़्या उन लोगों की है जो थोड़े समय के लिए घूमने या किसी काम से संयुक्त अरब अमीरात गए थे। इनमें ऐसे यात्री भी शामिल हैं जो किसी अन्य देश जाने के लिए वहां रुके हुए थे। इसके अलावा कई छात्र भी इस संकट में फंस गए हैं ज़्योंकि ईरानी हमलों के बाद कई शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ा है या पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यम से चलाया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के केवल दो दिन बाद ही करीब 22 हजार भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार से संपर्क कर देश लौटने की इच्छा जताई थी। यह संज़्या अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि खाड़ी क्षेत्र में बसे भारतीयों के सामने किस प्रकार की असुरक्षा और भय का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि पिछले तीन दिनों में कुछ अस्थायी और विशेष उड़ानों के जरिए करीब दस हजार भारतीयों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी हजारों लोग अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं और उनके लिए सुरक्षित वापसी की व्यवस्था अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। रिपोर्टों में बताया गया है कि दोहा से भी करीब 850 भारतीय नागरिकों ने घर लौटने की मांग की थी। वहां का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद होने के कारण उन्हें एक कठिन रास्ता अपनाना पड़ा। इन लोगों ने जमीन के रास्ते सऊदी अरब की सीमा पार की और फिर रियाद हवाई अड्डे से भारत के लिए उड़ान पकड़ी। यह पूरी प्रक्रिया बेहद कठिन और समय लेने वाली साबित हुई।

इसके अलावा दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे क्षेत्र के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर सामान्य उड़ान सेवाएं बंद रहने से हालात और उलझ गए हैं। कुछ उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह से संचालित की गई हैं, लेकिन उनकी संज़्या

बेहद सीमित है और उनसे सभी फंसे हुए यात्रियों को निकाल पाना लगभग असंभव नजर आ रहा है। देखा जाये तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता संयुक्त अरब अमीरात ही बना हुआ है। इसका कारण वहां रहने वाले भारतीयों की विशाल संज़्या है और साथ ही यह देश ईरान के हमलों की सीधी जद में भी रहा है। अनुमान के अनुसार केवल संयुक्त अरब अमीरात में ही तीस लाख से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं।

बताया जा रहा है कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई भारतीय अब जमीन के रास्ते देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संज़्या में लोग संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि ओमान के मस्कट हवाई अड्डे से भारत लौट सकें। लेकिन सीमा चौकियों पर भारी भीड़ और लंबी कतारों के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

इसी बीच, मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ओमान में प्रवेश करने से पहले यात्रियों के पास वैध भ्रमण वीजा होना अनिवार्य है। बिना वीजा के सीमा पार करने की कोशिश करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि खाड़ी सहयोग परिषद के छह देशों- संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत में इस समय लगभग एक करोड़ भारतीय रह रहे हैं। इस विशाल समुदाय की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार पर भारी दबाव बढ़ता जा रहा है।दूसरी ओर, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कुशलता भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्र में हो रहे किसी भी नकारात्मक घटनाक्रम को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। बढ़ते संकट के बीच मोदी सरकार ने सहायता के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है ताकि फंसे हुए भारतीय नागरिकों को तुरंत मदद और जानकारी मिल सके। पिछले कुछ दिनों में विशेष उड़ानों के जरिए मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु में यात्रियों को लाया गया है।

उधर, भारतीय दूतावास भी लगातार अपने नागरिकों से संपर्क बनाए हुए हैं और उन्हें सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने भी चेतावनी जारी कर कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय पूरी सतर्कता बरतें और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।बहरहाल, सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती जंग और हमलों के बीच हजारों भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए अब तक कोई व्यापक निकासी योजना घोषित नहीं की गई है। ऐसे में फंसे हुए भारतीयों की चिंता और गुस्सा दोनों लगातार बढ़ रहे हैं और वह अपने देश से जल्द और ठोस कदम की उज़्मीद कर रहे हैं।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

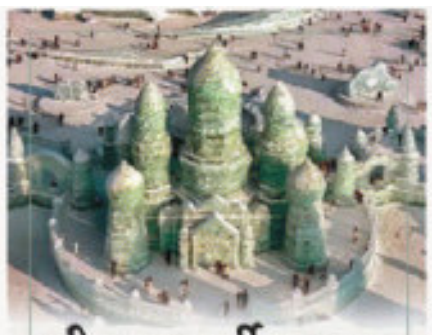

चीन का बर्फीला शहर कहलाता है हारबिन

हा रबिन चीन के सुदूर प्रवातरी भाग में स्थित हेइलोंगजियांग प्रांत की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर अपनी जमा देने वाली कड़ाके की सर्दियों के लिए जाना जाता है और इसे 'बर्फीला शहर' कहते हैं। रूस की नजदीकी के कारण यहां की इमारतों और संस्कृति पर रूसी प्रभाव नजर आता है। दुनिया का सबसे बड़ा आईस एंड स्नो शो यही पर सर्दियों के मौसम आयोजित फरवरी तक यह उत्सव चलता है। 1963 से यहां इस पर्व की शरुआत हुई थी। 2007 में इस दौरान यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ी बर्फ की शिल्पकारी भी की गई थी, जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया था। इसे 13000 क्यूबिक मीटर बर्फ का इस्तेमाल करके बनाया गया था। पहले यह पर्व सिर्फ चीन के लोगों के लिए ही था लेकिन अब दुनियाभर के करीब 18 लाख सैलानी इसका हिस्सा बनते है।

बांसुरी जैसा साज अलगोजा, देश के कई राज्यों का पारंपरिक वाद्य यंत्र

ह मारे देश में हर राज्य और क्षेत्र की अपनी पारंपरिक लोक कलाएं, संगीत और साज हैं। हर कला और हर साज की अपनी महता, बनावट और उसका अपना विशेष इतिहास है। देश के इन्हीं वाद्य यंत्रों में से एक खास साज है अलगोजा। दरअसल अलगोजा मुंह से फूंक मारकर बजाया जाने वाला बांसुरी के आकार-प्रकार का एक वाद्य यंत्र है, जिसका इस्तेमाल राजस्थानी कलाकारों के अलावा बलूच, पंजाबी, सिंधी, और कच्छी लोक संगीत में किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है यह। अलगोजा वादक घोघे खां जैसे कलाकारों ने इस साज को ऊंचाई दी लेकिन अब यह साज लुप्त होने की कगार पर है।

अलगोजा के हैं कई नाम

यह बांस से बना होता है और इसमें दो जुड़ी हुई चोंच वाली बांसुरियां होती हैं। इसे मटियान, गूही, पाव गूही, दो नाली, दोनल, गिर, सतारा या नागेज भी कहा जाता है। इसमें सुरों के लिए 7 से 9 छेद होते हैं। अलगोजा बजाने के लिए वादक दो अलगोजे मुंह में रखता है।

70 हजार कंकालों से सजा दुनिया का सबसे डरावना और रहस्यमयी चर्च

जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर, मुस्लिमों के लिए मस्जिद, पंजाबियों के लिए गुरुद्वारा है, वैसे ही इसाइयों के लिए चर्च है जहां जाकर भक्ति भाव का एहसास होता है और मन को सुकून पहुंचता है। मगर क्या आपने ऐसे चर्च के बारे में सुना या देखा है, जहां जिधर देखो उधर नर-कंकाल नजर आते हैं। यहां भक्ति भाव का नहीं बल्कि भय का एहसास होता है, मगर फिर भी उत्सुकता वश हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। आमतौर पर किसी भी जगह को सजाने के लिए फूलों या फिर अन्य सजावटी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च ही क्यों न हो। लेकिन दुनिया में एक ऐसा चर्च भी है, जो इंसानी कंकालों से सजा है। इसे बेहद ही डरावना और रहस्यमय चर्च माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहां लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, सालाना इस अनोखे चर्च को देखने के लिए दो लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं।

इस चर्च का नाम है सेडलेक ऑस्युअरी, जो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में है। बताया जाता है कि इस चर्च को सजाने के लिए 40 हजार से 70 हजार लोगों की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है। यहां छत से लेकर झूमर तक सबकुछ इंसानी हड्डियों से ही बनाए गए हैं। यही वजह है कि इसे 'चर्च ऑफ बोन्स' के नाम से भी जाना जाता है। यह चर्च आज से करीब 150 साल पहले यानी 1870 में बना है। दरअसल, इंसानी हड्डियों से इस चर्च को सजाने के पीछे एक बेहद ही रहस्यमय वजह है। सन् 1278 में बोहेमिया के राजा ओट्टोकर द्वितीय ने हेनरी नाम के एक संत को इंसाईयों की पवित्र भूमि यरुशलम भेजा था। दरअसल, यरुशलम को ईसा मसीह की कर्मभूमि कहा जाता है। यहीं पर उन्हें सूली पर भी चढ़ाया गया था। कहते हैं कि यरुशलम गए संत जब वापस लौटे तो वो अपने साथ वहां की पवित्र मिट्टी से भरा एक जार भी लेकर आए और उस मिट्टी को एक कब्रिस्तान के ऊपर डाल दिया। बस उसके बाद से यह लोगों के दफनाने की पसंदीदा जगह बन गई। कब्रिस्तान में पवित्र मिट्टी होने की वजह से लोग चाहते कि मरने के बाद उन्हें वहीं पर दफनाया जाए और ऐसा होने भी लगा। वहीं 14वीं और 15वीं शताब्दी में इस जगह पर प्लेग और युद्ध का आतंक फैल गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई और उन्हें

सेडलेक मे ही दफनाया जाने लगा। ऐसे मे पूरी जगह शमशान बन गई। बाद में चर्च बनाने का ख्याल आया, तब यह कार्य वहा के संतो को सौंप दिया, जो की कब्र में से हड्डियों को निकाल कर चर्च में रख देते थे। मगर 1870 में करीब 40000 लोगों की इन हड्डियो को कलात्मक रूप से सजाया गया और यह काम फ्रंटीसेक रिड ने किया था। वर्ष 1870 में फ्रेंटीसेक राइड ने करीब 70 हजार लोगों की हड्डियों को कलात्मक रूप से चर्च में सजाया। बाद में लोग इसे चर्च ऑफ बोन्स के नाम से जानने लगे। आज यह जगह ऑस्युअरी कहलाती है। सबसे पहले यहां शवों की अस्थाई रूप से कब्र बनाई जाती है। बाद में कुछ सालों बाद उनकी हड्डियां निकाल कर यहां चर्च में ऑस्युअरी में रखी जाती है। यह वह जगह है, जहां कब्र से कंकालो को निकालकर एक साथ रख दिया जाता है। चर्च को देखने हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं।

यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 'सेडलेक ऑस्युअरी' नामक एक ऐसा चर्च भी है जो मानव कंकाल और हड्डियों से बना हुआ है। इसमें 40 हजार लोगों की अस्थियों का इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय देश चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में बने इस चर्च को देखने दुनियाभर से लोग आते हैं। यह 1870 में बनाया गया, इसे 'चर्च ऑफ बोन्स' भी कहा जाता है। इसके निर्माण के पीछे की कहानी काफी रोचक है। बताते हैं कि 14वीं-15वीं शताब्दी में यहां प्लेग और युद्धों के कारण बहुत लोगों की मौत हुई। कब्रिस्तान में जगह नहीं बची तो लोगों के मन में एक ऑस्युअरी बनाने का ख्याल आया और यह काम पादरी को सौंप दिया गया। वे कब्रों से हड्डियां निकालकर ऑस्युअरी में रखने लगे। करीब 40 हजार लोगों की हड्डियां जमा हो गई तो उससे इस कलात्मक चर्च का निर्माण किया गया। मानव कंकाल यहां इस कलात्मक अंदाज से सजाए गए हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं।

वैन में बने 270 वर्गफीट के घर के लिए खरीदा 1.5 एकड़ का प्राइवेट आईलैंड

भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किस्से को शांति और सुकून की तलाश है। हर कोई इसे पाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका में रहने वाले टिम डेविडसन ने पहले शांति की तलाश में अपना घर छोड़कर 70 हजार डॉलर (51 लाख रुपए) में टिफनी वैन (पहियों पर बना घर खरीदा और बाद में इस वैन को पार्क करने के लिए फ्लोरिडा में 1.5 एकड़ (65 हजार 340 वर्ग फीट) में फैला आईलैंड खरीद लिया। इसके लिए उन्हें 2 लाख डॉलर भारतीय करेंसी के हिसाब से 1 करोड़ 46 लाख रुपए चुकाने पड़े थे। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने आसपास शोर पसंद नहीं है।

घर देखने आते हैं लोग

टिम के वैन में 270 वर्गफीट जगह है। इसी में उन्होंने अपना किचन, लिविंग स्पेस और वर्क स्पेस बना रखा है। इसके बाद वो एक जगह की तलाश में निकले जहां वो अपने इस छोटे से आशियाने को लेकर जा सकें। टिम का मानना है कि वो मिनिमलिस्ट है। यानी कि वो कम चीजो में जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। इसी वैन को उन्होंने अपना घर बनाया। उनके साथ इस काम में उनकी वाइफ सैम ने भी मदद की। ये छोटा सा घर इतना ज्यादा सेफ है कि उन्होंने पूरा लॉकडाउन यहीं बिताया। साथ ही साथ इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है।

तूफान से बचने के लिए एक और घर

आईलैंड में शिफ्ट होने के बाद टिम को एहसास हुआ कि अगर उन्हें आईलैंड पर रहना है तो तूफान से बचने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आईलैंड पर ही एक और घर भी इंस्टॉल किया है। यह घर 320 वर्ग फीट में बना है। इस घर की खास बात यह है कि यह अँक्टागन शेप में बना हुआ है। इस वजह से इस पर तूफान की हवाओं का असर कम होता है। इस घर को वो कम पैसे में सफर करने वालों को रहने के लिए देते हैं। यहां तक कि लोग टिम का घर दूर-दूर से देखने के लिए भी आते हैं। लंबी-लंबी लाइनें लगती है इस घर के डिजाइन को देखने के लिए।

लगाए फलों के पेड़

टिम ने जब आईलैंड खरीदा था तो उसमें घास और गंदगी थी। टीम ने इस साफ करने के साथ साथ इसमें शहर में मिलने वाली सभी सुविधाओं से जोड़ा। टीम ने अब इस आईलैंड को जीवंत जगह में बदल दिया है। यहां पर कई प्रकृति की खूबसूरत छटा देखने को मिलती है। उन्होंने आईलैंड पर आम, एवोकाडो, शहतूत, लीची, अनानास और अंजीर के काफी पेड़ लगाए हैं।

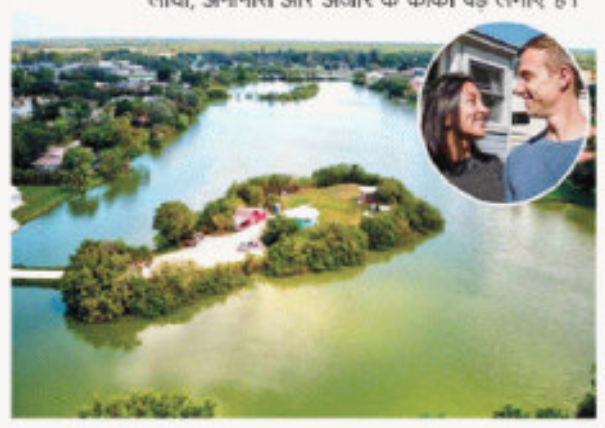

दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान की रहस्यमय बातें, 10 देशों में फैला है यह

सहारा मरुस्थल (रेगिस्तान) का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। दरअसल, सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द 'सहरा' से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। उत्तरी अफ्रीका पूरी तरह से इस रेगिस्तान से ढंका हुआ है जबकि इसका थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। आज हम आपको इस रेगिस्तान की कुछ खास और रहस्यमय बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे।

सहारा रेगिस्तान की लंबाई 4800 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह रेगिस्तान यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर और भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से भी अधिक है। यह करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान ने दुनिया के आठ फीसदी थलीय भाग को अपनी चपेट में ले रखा है। इसकी सबसे खास बात कि यह मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है, जिसमें माली, मोरक्को, मौरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल हैं।

भले ही सहारा रेगिस्तान में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां भी जीवित हैं। हालांकि पेड़ ज्यादातर पानी के स्रोतों के पास ही मिलते हैं। बाकी रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी और रात के समय भयंकर सर्दी पड़ती है। आमतौर पर रेगिस्तानों में बर्फबारी तो होती नहीं है, लेकिन साल 2016 में यहां बर्फबारी हुई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। इसके पीछे वजह ये बताई गई थी कि रेगिस्तान के पास ही स्थित एटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10-15 डिग्री नीचे चला गया था। साथ ही ऊंचाई पर कम दाब का केंद्र उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण हवा तेजी से नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थितियां पैदा हो गई। आज भले ही सहारा मरुस्थल वीरान और निर्जन दिखाई देता है, लेकिन करीब 6000 साल पहले यह हरा-भरा हुआ करता था। एक शोध के मुताबिक, अफ्रीका का सहारा क्षेत्र लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में बदल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका पता वैज्ञानिकों को आज तक नहीं चल सका है, क्योंकि इस बदलाव से जुड़े अधिकतर प्रमाण नष्ट हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि सहारा रेगिस्तान करीब 15000 साल के बाद फिर से हरा-भरा हो जाएगा।

कलिंग समाचार

संपादकीय

शनिवार 07 मार्च 2026

विदेश नीति को बदलते प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इतिहास में अपना नाम किन अक्षरों में दर्ज कराना चाहते हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन भारत की विदेश नीति का जो गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसे वो पूरी तरह मटियामेट करना चाहते हैं, यह साफ नजर आ रहा है। वैसे भी जब इतिहास की पूरी समझ न हो, या जानबूझकर इतिहास को नजरंदाज किया जाता है तो वर्तमान और भविष्य दोनों किस तरह खतरे में पड़ जाते हैं, इसका बड़ा उदाहरण नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा से मिल ही रहा है। महज दो दिनों के लिए मोदी इजरायल गए, लेकिन वहां जो कुछ उन्होंने कहा, उससे भारत की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया है। इजरायली संसद नेसेट में जिस तरह का भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, उसमें वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि इजरायल ने फिलीस्तीन में हमास को खत्म करने के नाम पर जो नरसंहार किया, उस पर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इजरायली संसद में जाकर हमास की न केवल आलोचना की, बल्कि तीन साल पहले 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की तुलना भारत में मुंबई के आतंकी हमले से कर दी। माना कि दोनों में निर्दोष लोगों की ही जान गई, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि नरेन्द्र मोदी को यूपीए सरकार में हुआ मुंबई हमला अगर याद आया तो खुद की सरकार में हुए पुलवामा और पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमलों को वो कैसे भूल गए। होता तो यही है कि इंसान को हाल की बात पहले याद आती है और पुरानी बात बाद में। लेकिन मोदीजी के साथ उल्टा ही हो रहा है। उन्हें अपने कार्यकाल का कुछ याद नहीं रहता, केवल कांग्रेस की सरकारों की बातें याद पड़ती हैं। अपने संबोधन में मोदी ने ग़ज़ा शांति पहल को क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक रास्ता बताया। यानी सीधे-सीधे अमेरिका की तारीफ उन्होंने की। इसके साथ ही इजरायल के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि कहीं भी आतंकवाद शांति को हर जगह खतरे में डालता है। गौर कीजिए कि मोदी ने इजरायल की कुर्बानियों का ज़िक्र किया लेकिन ग़ज़ा में मारे गए 70 हज़ार लोगों की हत्या और हमदर्दी के लिए एक शब्द नहीं कहा, वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें तो ट्रंप और नेतन्याहू से दोस्ती निभानी है। मोदी ने ग़ज़ा नरसंहार को पूरी तरह नज़रन्दाज़ किया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन दुख इस बात का है कि अपने साथ-साथ उन्होंने पूरे देश की जनता को इजरायल के साथ खड़ा दिखाया। मोदी ने कहा, %मैं भारत की जनता की ओर से हर खोई हुई जान के लिए गहरी संवेदना लेकर आया हूं और हर उस परिवार के लिए जिनका संसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बर्बर आतंकवादी हमले में टूट गया। हम आपका दर्द महसूस करते हैं। हम आपका दुख साझा करते हैं। भारत इजरायल के साथ मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ, इस पल में और उसके आगे भी खड़ा है। कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकता। कुछ भी आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता। कितने सुविधाजनक तरीके से मोदी ने ग़ज़ा में नेतन्याहू के इजरायली आतंकवाद का ज़िक्र तक नहीं किया। जबकि खुद इजरायल की जनता अपनी सरकार के ऐसे बर्बर रवैये के खिलाफ है। उन्हें अपने कार्यकाल का कुछ याद नहीं रहता, केवल कांग्रेस की सरकारों की बातें याद पड़ती हैं। अपने संबोधन में मोदी ने ग़ज़ा शांति पहल को क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक रास्ता बताया। यानी सीधे-सीधे अमेरिका की तारीफ उन्होंने की। इसके साथ ही इजरायल के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि कहीं भी आतंकवाद शांति को हर जगह खतरे में डालता है। गौर कीजिए कि मोदी ने इजरायल की कुर्बानियों का ज़िक्र किया लेकिन ग़ज़ा में मारे गए 70 हज़ार लोगों की हत्या और हमदर्दी के लिए एक शब्द नहीं कहा, वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें तो ट्रंप और नेतन्याहू से दोस्ती निभानी है।

आयातित विदेशी हथियारों पर भारत की निर्भरता चिंता की बात

नन्तू बनर्जी

भारत अभी भी चीन और पाकिस्तान जैसे बहुत ज़्यादा लड़ाकू पड़ोसियों से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा विदेशी आयात पर निर्भर है। स्वदेशीकरण के तथाकथित दबाव के बावजूद, भारत, चीन और पाकिस्तान से दोहरे खतरों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी प्रौद्योगिकी, जेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी काफी हद तक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की नई मंजूरी से ज़्यादा उत्साहित होने की कोई बात नहीं है, जिसकी कीमत 3.25 लाख करोड़ रुपये (लगभग 40 अरब डॉलर) है, जिसे %सभी डिफेंस डील्स की सबसे बड़ी डील% कहा जा रहा है।

यह बड़ी चिंता की बात है कि देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी, यूक्रेन की तरह भारत को भी अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए आयातित हथियारों पर निर्भर रहना पड़ता है- फ्रांस से राफेल, संयुक्त राज्य अमेरिका से पोसाइडनजेट, और रूस से एस-400ट्राय फ जैसे कई दूसरे हथियार। यहां तक कि उन क्षेत्रों जहां भारत विदेशी सहयोग से रक्षा उपकरण बना रहा है, में भी देश अभी भी विदेशी सबसिस्टम पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। हालांकि एयरक्रा ट और जहाज़ जैसे प्लेटफॉर्म भारत में असेंबल किए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी हाई-एंड कंपोनेंट अभी भी आयातित किए जाते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला कमज़ोर हो जाती है। पिछले कुछ सालों में, भारत ने कई राफेल सौते किए हैं। इनमें लगभग 7.87 अरब यूरो (लगभग 58,891 करोड़ रुपये) के 36जेट शामिल हैं और हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 26 नेवल वेरिएंट के सौदे हुए हैं, जिसकी कीमत 64,000 करोड़ रुपये है। भारत में बने जेट के साथ क्वालिटी एश्योरेंस के मुद्दों पर कई सालों तक बातचीत चलने के बाद भारत ने 2015 में फ्रांस से 126 राफेल फाइटर खरीदने के समझौते को रद्द कर दिया था।

1950 में, पड़ोसी चीन की अर्थव्यवस्था और रक्षा भारत की तुलना में बहुत कमजोर थी। आज, चीन खुद को अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की सबसे सेल्फ-प्रोपेल्ड घातक मिलिटरी ताकतों में से एक मानता है।

भारत के आयात पसंद करने वाले राजनीतिक शासकों की वजह से, देश को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नालॉजी, खासकर जेट इंजन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्डऐरे (एईएसए) रडार, मिसाइल सीकर और स्टील्थ टेक्नालॉजी विकसित करने में बड़ी कमियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास खर्च दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। डीआरडीओ को 2025-26 में कुल रक्षा बजट का सिर्फ 3.94 प्रतिशत मिलेगा।

लंबे खरीद चक्र और आर एंड डी परियोजनाओं में बहुत ज़्यादा देरी से आधुनिकीकरण में रुकावट आ रही है। भारत के पास यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए काफ़ी, विश्व स्तरीय परीक्षण अवसंरचना भी नहीं है, जिससे देशी उत्पादनों के विकास और प्रमाणीकरण में कमी आ रही है।

भारत के लगभग 80 प्रतिशत रक्षा उपकरण रूस के होने के कारण, रूस देश की रक्षा क्षमताओं का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। रूस तब सामने आया जब पश्चिमी मिलिटरी ताकतों ने भारत को हाई-एंड हथियार आपूर्ति करने से लगभग मना कर दिया था। भारत-रूस रक्षा भागीदारी सिर्फ खरीदार-विक्रेता संबंध से बढ़कर संयुक्त विकास और उत्पादन तक फैली हुई है। भारत में मौजूद बड़े खतरनाक रूसी प्लेटफॉर्म में सुखोई एसयू-30एमकेआई (जो रूस की मदद से भारत में बना), टी-905 %भीष्म' और टी-22मु य लड़ाकू टैंक, ब्रह्मोसक्रूज़ मिसाइल, रूस में बनी सबमरीन, जिसमें लीज़ पर लिए गए न्यूक्लियर-पावर्ड जहाज़ (अकुला-2) और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्रा ट कैरियर और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एमआई-17परिवहन हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

लंबे समय तक, भारत ने अपने निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में आने नहीं दिया, हालांकि वह हथियारों और गोला-बारूद के आयात के लिए विदेशी निजी कंपनियों के साथ सौदा करने में हमेशा खुश था। इत्तेफ़ाक से, डसॉल्ट एविएशन का मालिकाना हक मु य रूप से एक फ्रेंच फैमिली होल्डिंग कंपनी, ग्रुप इंडस्ट्रियल मार्सेलडसॉल्ट (जीआईएमडी) के पास है।

कंपनी पर परिवार का कड़ा नियंत्रण है, जिसके पास लगभग 67प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। एयरबस के पास लगभग 10प्रतिशत शेयर हैं। भारत में रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 2024-25 में कुल उत्पादन का सिर्फ 23प्रतिशत थी, जिसमें ज़्यादातर लो-एंड उत्पादन थे। यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए विश्वस्तरीय परीक्षण अवसंरचना की कमी से देशी उत्पादन के विकास और प्रमाणीकरण में देरी होती है। शुरू में, चीन भी रूसी रक्षा आपूर्ति पर निर्भर था। लेकिन, क युनिस्ट शासन ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बहुत प्राथमिकता दी और सालों से रक्षा उत्पादनों की हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया भर में एक बड़ा दावेदार बन गया।

चीन का एक लो-टेक हथियार आयातक से एक हाई-एंड देशी डिफेंस मैन्युफैक्चरर और निर्यातक बनना एक लंबे समय की, सरकार की बनाई रणनीति से हुआ है, जिसमें अनुसंधान और विकास में भारी निवेश, इंटेंस मिलिट्री-सिविल यूजन (एमसीएफ), और विदेशी प्रौद्योगिकी का लक्षित प्रदर्शन शामिल है। पिछले दस सालों में, चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनकर उभरा है, जिसके पास स्टील्थ फाइटर्स (जे-20, जे-35), एयरक्रा ट कैरियर (फुजियान), और हाइपरसोनिक मिसाइलों की क्षमता है जो पश्चिमी प्रौद्योगिकी की बेहतरी को चुनौती देते हैं।

तकनीक गाइड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) के वैश्विक हथियारों के हस्तांतरण, निर्यात मात्रा और अतिविकसित सैन्य प्रौद्योगिकी के विकास के आंकड़े के आधार पर, हाई-एंड डिफेंस इक्विपमेंट (2020-2024) बनाने वाले सर्वोच्च 10 देशों में एयरोस्पेस, नेवल और मिसाइल प्रौद्योगिकी में भारी निवेश करने वाली बड़ी ताकतें सबसे ज़्यादा हैं। ये देश हैं-यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, स्पेन और साउथ कोरिया।

हालांकि, भारत अभी भी चीन और पाकिस्तान जैसे बहुत ज़्यादा लड़ाकू पड़ोसियों से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा विदेशी आयात पर निर्भर है।

स्वदेशीकरण के तथाकथित दबाव के बावजूद, भारत, चीन और पाकिस्तान से दोहरे खतरों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी प्रौद्योगिकी, जेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी काफी हद तक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। यह निर्भरता सीमा विवाद, सीमा पार से आतंकवाद और अस्थिर पड़ोसी के साथ बनी हुई है। जबकि 3,488 किलो मीटर भारत-चीन सीमा (एलएसी) पर तनाव सालों से बना हुआ है, पाकिस्तान से भी सीमा-पार आतंकवाद के लिए लगातार तैयार रहने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हाई-एंड घरेलू रक्षा विनिर्माण में बड़ा निवेश करे। हाई-एंड सैन्य प्रौद्योगिकी में अंतर को कम करना अब देश के लिए एक असली चुनौती है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के अप्रत्याशित विजेता हैं राहुल गांधी

के रवींद्रन

आखिरकार, गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता में बढ़ोतरी एक ज़रूरी सच्चाई को दिखाती है= लोकतांत्रिक राजनीति में, असहमति- जब पक्के यकीन और असर के साथ कही जाए- तो नेताओं को ऊपर उठा सकती है और बहस को नई दिशा दे सकती है। यह पल भारतीय राजनीति में एक स्थायी मोड़ बनेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और विपक्ष दोनों इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के आस-पास चल रही राजनीतिक कहानी ने टैरिफ, बाजार में पहुंच और राजनयिक गठजोड़ पर बहस छेड़ने से कहीं ज़्यादा असर डाला है। इसने भारत के घरेलू राजनीतिक माहौल की रूपरेखा को बदल दिया है, खासकर राहुल गांधी का कद मु य विपक्षी नेता के तौर पर बढ़ाकर। मोदी सरकार ने व्यापार समझौते को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया है, जो 30 ट्रिलियन डालर के अमेरिकी बाजार में खास पहुंच की रणनीतिगत और आर्थिक मूल्य को दिखाता है।

इस समझौते के फ़ायदों को बताते हुए, मोदी प्रशासन एक बड़ा दावा कर रहा है= कि भारत के लंबे समय के आर्थिक फ़ायदे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा करीब से जुड़ने से ही सबसे अच्छे ढंग से पूरे होंगे। कई खरब डॉलर के बाजार पर ज़ोर, आकांक्षा और विकास की एक लोकलुभाऊ कहानी को दिखाता है। फिर भी, इस कहानी को बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ा गया है। राहुल गांधी की इस समझौते की ज़ोरदार आलोचना, जिसमें उनकी भावनाओं और राजनीतिक संवेदनाएं जुड़ी हैं - और जिसमें उनका यह कहना कि यह %भारत माता' को बेचने जैसा है, ने एक तकनीकी नीति चर्चा को राष्ट्रीय पहचान, स प्रभुता और राजनीतिक नेतृत्व पर एक बड़े मुकाबले में बदल दिया है।

खास बात सिर्फ गांधी की आलोचना का तथ्य ही नहीं है, बल्कि उसे मिली राजनीतिक पकड़ भी है। पारंपरिक रूप से, इस कांग्रेस नेता को कई जानकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक दबदबे के मुकाबले कम मज़बूत विरोधी के तौर पर दिखाया है। हालांकि, व्यापार समझौते पर उनके रुख ने भद्रलोक के राजनीतिक दायरे और आम जनता के कुछ हिस्सों में भी इस सोच को बदल दिया है। सरकार के तौर-तरीके को ज़ोरदार ढंग से चुनौती देकर, गांधी ने राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक बराबरी को लेकर बुनियादी चिंताओं को छुआ। उनकी टिप्पणी उन लोगों को पसंद आई जो वैश्वीकरण के अलग-अलग फ़ायदों से सावधान थे और उन समझौतों पर शक करते थे जिन्हें भद्रलोक के हितों के लिए या राणनीतिगत स्वायत्तता से समझौता करने वाला माना जाता था। ऐसा करके, उन्होंने बहस को व्यापारिक घाटे और टैरिफ लागू किये जाने की निर्धारित अवधि तक सीमित न रखकर इस बड़े सवाल से जोड़ दिया कि भारत का आगे का रास्ता कौन तय करेगा।

गांधी की आलोचना पर सरकार की प्रतिक्रिया ज़ोरदार और बिना रुके रही है। सत्ताधारी पार्टी की मशीनरी, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के प्रवक्ता और उससे जुड़े मीडिया शामिल हैं, ने समझौते के उनके विरोध को बदनाम करने के लिए कमर कस ली है। यह बचाव का रवैया न केवल एक तीखे राजनीतिक जवाब का संकेत देता है, बल्कि गांधी की बढ़ती पहचान के नतीजों को लेकर एक बड़ी चिंता का भी संकेत देता है। उन्हें गैर-ज़ि मेदार या देशद्रोही बताने की उनकी लगातार कोशिशें इस बात की जानकारी दिखाती हैं कि गांधी की आलोचना ने सरकार की शुरुआती सोच को तोड़ दिया है और एक ज़्यादा विवादित सार्वजनिक बातचीत को मजबूर किया है।

इस प्रक्रिया में, गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता को काफी बढ़ावा मिला है। एक मामूली या बेअसर विपक्षी नेता के तौर पर खारिज किए जाने के बजाय, अब वह सरकार की एक अहम नीतिगत उपलब्धि के बारे में हो रही बातचीत में एक केन्द्रीय जगह पर हैं। एक तरफ, इसने ऐसे समय में विपक्ष की आवाज़ को और तेज़ कर दिया है जब सरकार को अपनी विदेश नीति पहल पर बड़ी आम सहमति की उ मीद थी। दूसरी तरफ, इसने आ यान पर सरकार के नियंत्रण की सीमा को भी सामने ला दिया है। भारत-अमेरिका समझौते के फायदों को ज़ोर-शोर से आगे बढ़ाकर, मोदी प्रशासन का मकसद अपनी राजनयिक समझ और आर्थिक दृष्टिकोण को दिखाना था। फिर भी, गांधी की आलोचना पर जो ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है, उससे पता चलता है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा- या कम से कम राजनीतिक वर्ग- अलग-अलग सोच को मान रहा है। इससे पता चलता है कि भूमंडलीकरण और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर लोगों की राय सरकार के संदेश से कहीं ज़्यादा उलझन भरी और विवादित है। जब व्यापार राष्ट्रीय गर्व और राजनीतिक पहचान से जुड़ जाता है, तो आर्थिक नीति पर बहस तकनीकी खोखलेपन में नहीं चलती; बल्कि वे बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्षों का मैदान बन जाती है। ज़्यादा जानें ताज़ा समाचार कविता संग्रह समाचार संग्रह मोदी और उनकी पार्टी के लिए, अब चुनौती अपने तौर-तरीके को फिर से ठीक करने की है। राहुल गांधी के खिलाफ मौजूदा ज़ोरदार विरोध एक ताकतवर संस्था के सामने खड़े होने वाले अंडरडॉग के तौर पर उनकी हैसियत को और मज़बूत करने से उल्टा पड़ सकता है। सरकार के लिए खतरा यह है कि उनकी आलोचना को कम करने की कोशिश में, वे अनजाने में उसे सही ठहराते हैं। इस मुद्दे पर राहुल गांधी को बार-बार लक्षित करने से वे विरोध का केंद्र बन सकते हैं, और ऐसे समर्थकों को बढ़ावा मिल सकता है जो उनके विरोध को मौकापरस्त के बजाय उसूलों पर आधारित मानते हैं। ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय की बातें काफी मायने रखती हैं, और राहुल गांधी को किसी विदेशी ताकत को दी जा रही कथित छूट के खिलाफ भारत की इज्ज़त के रक्षक के तौर पर पेश करने के दूरगामी असर हो सकते हैं। इस राजनीतिक नाटक का बड़ा मतलब यह है कि आर्थिक राजनयिकता को घरेलू वैधता से अलग नहीं किया जा सकता। भारत-अमेरिका समझौते पर बहस यह दिखाती है कि कैसे वैश्विक आर्थिक नीतियां राष्ट्रीय चरित्र, नेतृत्व की विश्वसनीयता, और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के सवालों से अलग नहीं हो सकती। मोदी सरकार के लिए, अमेरिकी बाजार में खास पहुंच पाना एक रणनीतिगत प्राथमिकता बनी हुई है। राहुल गांधी के लिए, उसी समझौते की आलोचना ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का एक अनोखा मौका दिया है। आखिरकार, गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता में बढ़ोतरी एक ज़रूरी सच्चाई को दिखाती है= लोकतांत्रिक राजनीति में, असहमति- जब पक्के यकीन और असर के साथ कही जाए- तो नेताओं को ऊपर उठा सकती है और बहस को नई दिशा दे सकती है। यह पल भारतीय राजनीति में एक स्थायी मोड़ बनेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और विपक्ष दोनों इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अभी के लिए, राजनीतिक मैदान में सबसे ज़्यादा फ़ायदा राहुल गांधी को मिल रहा है, जिनकी समझौते को चुनौती ने उनकी आवाज़ को और मज़बूत किया है और राष्ट्रीय बातचीत में उनकी भूमिका को नया रूप दिया है।

ट्रंप का असली चेहरा सामने आया

शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करने की तमन्ना लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने %ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व% चलाकर वेनेजुएला पर शनिवार स्थानीय समय के अनुसार 02=01 बजे हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया लोरेस समेत गिर तार कर लिया और उन्हें हवाई मार्ग से अमेरिका ले आया गया। अमेरिकी विमान से मादुरो को जब उतारा जा रहा था तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हथकड़ियां भी लगी थीं। यह दृश्य देखकर इतिहास खुद को दोहराता है, वाली मिसाल याद आ गई। लेकिन यह नहीं पता था कि इतिहास इतनी जल्दी दोहराया जाएगा। अभी 21वीं सदी शुरु ही हुई थी कि इराक पर अमेरिका ने विनाशकारी हथियारों की तलाश के नाम पर आक्रमण किया और तत्कालीन शासक सद्दाम हुसैन को गिर तार कर फांसी पर भी चढ़ा दिया।

फिर पता चला कि ऐसे कोई हथियार इराक में थे ही नहीं। शायद अमेरिका को हथियारों की तलाश थी भी नहीं, उसे इराक के प्राकृतिक संसाधनों का कब्जा चाहिए था, जो उसे मिल गया। यही खेल अब वेनेजुएला में खेला गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर गलत तरीके से सत्ता हथियाने का आरोप लगाने के साथ ड्रग्स तस्करी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और उनका कहना है कि अब मादुरो को पत्नी समेत अमेरिका की कड़ी न्याय व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा।

मानो सारी दुनिया का ठेका अमेरिका को मिल चुका है कि उसका राष्ट्रपति जब चाहे किसी संप्रभु देश पर आक्रमण कर दे और वहां के नेता को अमेरिकी कटघरे में खड़ा कर दे। और अंतरराष्ट्रीय कानूनों, स्त्री अधिकार को ठेंगा दिखाते हुए राष्ट्र प्रमुख के साथ उनकी पत्नी को भी गिर तार कर ले। चिंता की बात यह है कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जिन उद्देश्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को बनाया गया था, वह पूरी तरह नख-दंत विहीन और लाचार बन चुकी है। घर के अशक्त बूढ़े बुर्जुग उपद्रवी बच्चों को मत लड़ो-मत लड़ो जैसी लाचारगी भरी नसीहत देते हैं, वैसा ही हाल संरा का हो चुका है।पूरी दुनिया में अमेरिका समर्थित हमले हो रहे हैं और संरा बयान जारी करने से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। इससे बेहतर है कि संरा को मिटा कर नए सिरे से कोई ऐसी वैश्विक संस्था बनाई जाए, जो वाकई दुनिया में शांति स्थापना का काम कर सके। लेकिन इसकी पहल कौन करेगा ये भी विचारणीय है।

विविध समाचार

आपातकाल के दौरान जेलें काटने वाले संघर्षशील योद्धाओं को एमपी और हरियाणा की भाजपा सरकार की तरह पेंशन दे मान सरकार : हरदेव सिंह उभ्भा

चंडीगढ ०६/०३ (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश प्रेस सचिव हरदेव सिंह उभ्भा ने कहा है कि देश में आपातकाल के दौरान जेलें काटने वाले संघर्षशील योद्धाओं के साथ पंजाब सरकार द्वारा लगातार अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले इन योद्धाओं को आज तक उनका उचित सम्मान और पेंशन नहीं मिली। उभ्भा ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में आपातकाल संघर्षशील योद्धाओं के लिए पेंशन योजनाएँ लागू हैं, लेकिन पंजाब में इस मामले को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन संघर्षशील योद्धाओं ने जेलों में वर्षों तक कष्ट सहे, वे आज भी बुजुर्ग अवस्था में दर–दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। भाजपा नेता हरदेव उभ्भा ने कहा कि मध्य प्रदेश और हरियाणा की भाजपा सरकार की तरह भगवंत मान सरकार भी 30 हजार रुपये प्रति माह पेंशन दे। हरदेव सिंह उभ्भा ने कहा कि विभिन्न राज्यों में आपातकाल योद्धाओं को 10 हजार से 30 हजार रुपये तक पेंशन दी जा रही है, लेकिन पंजाब सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि वह केवल वादे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। हरदेव सिंह उभ्भा ने मांग की कि पंजाब सरकार तुरंत आपातकाल संघर्षशील योद्धाओं के लिए पेंशन योजना लागू करे और उन्हें उनका बनता सम्मान प्रदान करे। उन्होंने कहा कि भाजपा आपातकाल संघर्षशील योद्धाओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आवाज बुलंद करती रहेगी।

राष्ट्रीय युवा दिवस पर सुखना लेक में 'विकसित भारत मैराथन' का आयोजन

चंडीगढ ०६/०३ (संवाददाता): अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) एवं विद्यार्थी कल्याण ट्रस्ट की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 'विकसित भारत' की संकल्पना को जन–जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से सुखना लेक, चंडीगढ़ में 'विकसित भारत मैराथन' का आयोजन किया गया। मैराथन में चंडीगढ़ के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से 1,500 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया और युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ–साथ राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मैराथन का शुभारंभ राज्यसभा सांसद श्री सतनाम सिंह संधू और एबीवीपी पंजाब प्रांत अध्यक्ष प्रो. प्रशांत गौतम ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रप्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं तथा 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने में सहायक हैं। इस आयोजन के मुख्य प्रायोजक राज मल्होत्रा आईएएस अकादमी और वीटा रहे, जिनके सहयोग से कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो सका। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री आदित्य तकियार ने कहा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

डबल इंजन सरकार किसानों के सम्मान व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध : नायब सिंह सैनी

चंडीगढ ०६/०३ (संवाददाता): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनबंधु चौधरी छोटूराम के संघर्षों से किसान और मजदूर के जीवन में निर्णायक बदलाव आया। कृषि भूमि की रक्षा किसान की गरिमा और मेहनतकश की इज्जत उनके जीवन के मूल मंत्र थे। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए डबल इंजन सरकार किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को कुरुक्षेत्र स्थित अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी तथा सांसद सुभाष बराला ने दीनबंधु सर छोटूराम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला को 31 लाख रुपये तथा सांसद सुभाष बराला ने 21 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी और दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका जीवन साहस, संवेदना और सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए प्रभावी कानून बनाए और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं।

प्रदेश में 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। सरकार ने अब तक फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपये किसानों को दिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक–2024 पारित कर पट्टेदार किसानों को कानूनी सुरक्षा दी गई है। 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' पोर्टल से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।

गोल्डन टेंपल सरोवर में कुल्ला करने वाले को निहंगों ने जड़ा थप्पड़, माफी मंगवाकर पुलिस को सौंपा

अमृतसर/गाजियाबाद ०६/०३ (संवाददाता):। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर (गोल्डन टेंपल) के पवित्र सरोवर में कुल्ला करने और उसका वीडियो वायरल करने वाले मुस्लिम युवक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में निहंग सिखों ने उक्त युवक को पकड़ लिया। निहंग विक्की थॉमस की मौजूदगी में युवक का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उसे एक निहंग द्वारा थप्पड़ जड़ते हुए देखा गया। निहंगों ने युवक और वीडियो बनाने वाले उसके साथी को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। इसके बाद निहंगों ने उसे गाजियाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और अब उसे अमृतसर पुलिस को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी अब सख्त रुख अपनाते हुए अमृतसर पुलिस के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है। SGPC ने जब अपने स्तर पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मामले की जांच की, तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। जांच में पता चला कि आरोपी युवक करीब 20 मिनट तक गोल्डन टेंपल परिसर में मौजूद रहा, लेकिन इस दौरान उसने एक बार भी परिक्रमा नहीं की और न ही गुरु घर में माथा टेकने की कोशिश की। SGPC का कहना है कि उसका व्यवहार और गतिविधियां साफ इशारा करती हैं कि वह केवल बेअदबी करने और माहौल खराब करने की नीयत से ही वहां पहुंचा था। गौरतलब है कि इससे पहले युवक ने सोशल मीडिया पर दो बार माफी मांगी थी, लेकिन सिख समुदाय ने उसे स्वीकार नहीं किया। पहली बार उसने जेब में हाथ डालकर माफी मांगी थी और दूसरी बार भी उसका रवैया समुदाय को नागवार गुजरा था। वहीं, इस मामले में शुरुआत में कोई ठोस कानूनी कार्रवाई न करने पर SGPC की भी कड़ी आलोचना हो रही थी। संगत का सवाल था कि जब गुजरात की अर्चना मकवाना द्वारा योग करने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, तो सरोवर की मर्यादा भंग करने वाले इस युवक पर नरमी क्यों बरती गई। इसी ढिलाई को देखते हुए निहंगों ने पहले गाजियाबाद प्रशासन को शिकायत दी थी। गाजियाबाद में युवक को पकड़ने के बाद निहंगों ने स्पष्ट किया कि युवक की हरकत से सिखों की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर सिख समुदाय पर जोश में आकर कानून हाथ में लेने के आरोप लगते हैं, इसलिए उन्होंने संयम बरतते हुए सबसे पहले कानून के दायरे में रहकर पुलिस से संपर्क किया। निहंगों की मांग थी कि युवक सार्वजनिक रूप से सिख मर्यादा के अनुसार अपनी गलती स्वीकार करे। फिलहाल गाजियाबाद के अंकुर विहार थाने की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पंजाब में पूर्व महिला सरपंच की गोली मारकर हत्या, पति बाल–बाल बचा, पुरानी रंजिश में पड़ोसियों पर फायरिंग का आरोप

मानसा ०६/०३ (संवाददाता): पंजाब के मानसा जिले में शनिवार को दिनदहाड़े हुई एक वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। गांव खिल्लन में आपसी रंजिश का एक खौफनाक अंजाम देखने को मिला, जहां पूर्व महिला सरपंच की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने का आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि उनके पड़ोसियों पर ही लगा है। मृतका की पहचान 45 वर्षीय महेंद्रजीत कौर के रूप में हुई है। हमलावरों ने न केवल महिला को निशाना बनाया बल्कि उनके पति पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से गोली गाड़ी में लगने की वजह से उनकी जान बच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब पूर्व सरपंच महेंद्रजीत कौर अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से आए हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से महेंद्रजीत कौर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, उनके पति पर चलाई गई गोली निशाने से चूककर गाड़ी पर जा लगी, जिससे वह बाल–बाल बच गए। दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस की शुरुआती जांच और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, इस हत्या के तार पुरानी रंजिश से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार और आरोपी पक्ष (पड़ोसियों) के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इससे पहले भी पूर्व सरपंच के परिवार के एक सदस्य की हत्या की जा चुकी है, जिसके चलते इस घटना को गैंगवार या बदले की भावना से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक हत्या के पुख्ता कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुरानी दुश्मनी को ही मुख्य वजह माना जा रहा है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही मानसा पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने खून से लथपथ पूर्व सरपंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है।

हर हिस्से में हवा और पानी के प्रदूषण की स्थिति

मध्य प्रदेश में देश के सबसे स्वच्छ शहर का कई बरसों से अवार्ड जीत रहे इंदौर में दूषित पानी पीने से एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई। साल का अंत और नए साल की शुरुआत इसी खबर से हुई है। पता नहीं चल पा रहा है कि पीने के पानी की सप्लाई में जहरीला पानी कहां से मिज़्स हुआ। लेकिन खबर है कि दो महीने से लोग पानी के दूषित होने की शिकायत कर रहे थे। पानी से बदबू आ रही थी और लोगों की तबियत बिगड़ रही थी। अब खबर है कि पानी में एसिड और बैज़्टीरिया की भारी मात्रा मिली है। लेकिन तय मानें कि इसके लिए किसी को जिज़्मेदार नहीं माना जाएगा। एकाध लोगों के तबादले होंगे और एकाध लोग निलंबित उसके बाद सब रफा दफा हो जाएगा। दूसरी खबर है कि राजधानी दिल्ली की, जहां पिछले ढाई महीने से हवा जहरीली बनी हुई है। वायु गुणवज़ा सूचकांक यानी एज़्यूआई चार सौ के आसपास है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री का दावा है कि पिछले आठ साल में सबसे कम कम पीएम 2.5 पिछले साल यानी 2025 में रहा। उनके हिसाब से एक ज़्यूबिक मीटर में पीएम 2.5 की मात्रा एक सौ के करीब है। सोचें, भारत सरकार का मानक प्रति ज़्यूबिक मीटर पीएम 2.5 की मात्रा 60 रखने का है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक 12 का है। लेकिन एक सौ होने को उपलज़्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह पूरे साल का औसत आंकड़ा है। पिछले ढाई महीने का औसत आंकड़ा तीन सौ से ऊपर का है। यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है देश के हर हिस्से में हवा और पानी के प्रदूषण की यही स्थिति है। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सात से आठ हमेशा भारत के होते हैं। सूची जितनी लंबी होती जाती है, भारत के शहरों की संज़्या उतनी बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि भारत के उन शहरों में प्रदूषण है, जहां उद्योग लगे हैं। बिहार के ऐसे शहर, जहां दूर दूर तक कोई फैज़्टरी नहीं है वहां भी एज़्यूआई चार सौ से ऊपर है और इसका कारण सिर्फ इतना है कि चारों तरफ धूल मिट्टी फैली है और निर्माण कार्यों से होने वाला प्रदूषण धूल की चादर की तरह फैला हुआ है। किसी भी शहर में नगर निगम को सफाई से कोई लेना देना नहीं है। राजधानी दिल्ली में सैकड़ों टन कूड़ा रोज निकलता है, जिसका बड़ा हिस्सा सड़कों पर बिखरा रहता है। हर साल सर्दियों में कभी पटाखों पर तो कभी किसानों की पराली पर प्रदूषण का दोष मढ़ दिया जाता है। लेकिन अभी न तो पटाखे चल रहे हैं और न पराली जलाई जा रही है फिर भी एज़्यूआई चार सौ के करीब है। ये दो प्रतिनिधि घटनाएं हैं, जो बताती हैं कि भारत में प्रकृति कम आपदा पैदा कर रही है और व्यवस्था ज्यादा आपदा पैदा कर रही है। जहरीला पानी व्यवस्था से उपजी आपदा है तो दिल्ली का प्रदूषण भी व्यवस्था की वजह से है। गाड़ियों के अंधाधुंध रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। सड़क पर चलने की जगह नहीं है और न किसी के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह है। लेकिन गाड़ियां निकल रही हैं और उनके धुएं से देश की हवा प्रदूषित हो रही है।

सज़्सिडी के बाद भी ईवी गाड़ियों की संज़्या नहीं बढ़ रही है लेकिन जीएसटी में कटौती हुई तो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बेतहाशा बिक्री हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में हर साल बारिश के साथ भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाएं हो रही हैं तो यह भी प्रकृति से ज्यादा मानवीय आपदा है। उज़राखंड में टिहरी में पानी रोकने से बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं तो पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण और जंगलों की कटाई ने पहाड़ों को कमजोर किया है। दशकों से नदियों की सफाई नहीं होने से सभी नदियों में गाद जमी है, जिसकी वजह से नदियों में बारिश का पानी नहीं रूकता है और बाढ़ आती है। भारत की भीड़ किस तरह से कुव्यवस्था की गुलाम है इसका सबूत पिछले दिनों मिला, जब इंडिगो का संकट खड़ा हुआ। एक निजी कंपनी ने सरकार के आदेश का पालन नहीं करने का फैसला किया। उसने जरूरी संज़्या में पायलट नहीं भरती किए और जब ड्यूटी के नए नियम लागू हुए तो उसने उड़ानें रद्द करनी शुरू की। उसने एक दिन में एक एक हजार उड़ानें रद्द की। पैसे और रसूख वाले लोग हवाईअड्डों पर भेड़ बकरियों की तरह घूम रहे थे। हजारों लोगों परिवार के साथ कई कई दिन तक हवाईअड्डों पर फंसे रहे तो हजारों लोगों के बैगेज कई दिनों तक नहीं मिले। नागरिक असहाय तो सरकार भी असहाय।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार राउरकेला, शनिवार 07 मार्च 2026

मयूरभंज में जादू-टोना के शक में बुजुर्ग महिला को जलाकर मार डाला गया

बारीपदा ०६/०३ (संवाददाता): अंधविश्वास से जुड़ी एक और परेशान करने वाली घटना में, मयूरभंज जिले में जादू-टोना करने के शक में एक अविवाहित बुजुर्ग महिला की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। यह घटना बहलदा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुंभिरदा गांव में हुई। मृतक की पहचान जाबा टुडू के रूप में हुई है, जबकि आरोपी, उसका पड़ोसी युगु मरंडी, ने अपराध के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी को महिला पर डायन होने का शक था। शुक्रवार देर रात, जब पीड़िता अपने घर में अकेली सो रही थी, तो आरोपी ने कथित तौर पर उस पर हंसिया से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान उसने उसे आग भी लगा दी, जिससे उसकी बेरहमी से मौत हो गई।सूचना मिलने पर, बहलदा पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। शनिवार सुबह, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस जदुनाथ जेना और रायरंगपुर स्ष्ठक्क बीरेंद्र कुमार सेनापति, एक साइंटिफिक टीम के साथ, घटनास्थल की जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए गांव गए। बॉडी को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, और घटनाओं के सही क्रम और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। जादू-टोना के खिलाफ जागरूकता कैंपेन और कानूनी नियमों के बावजूद, राज्य के कुछ इलाकों में अंधविश्वास से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास के बने रहने पर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं।

शादी की दावत में फ़ूड पॉइज़निंग का डर, 25 से ज़्यादा मेहमान बीमार पड़े

अंगुल ०६/०३ (संवाददाता): ज़िले के टुबे गांव में एक शादी की दावत के बाद 25 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए, जिससे दहशत फैल गई। करीब 20 मरीज़ों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्कार्टर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यह दावत जरापाड़ा पुलिस की सीमा में हुई। रिश्तेदार, दोस्त और गांव वाले जश्न के लिए इकट्ठा हुए, जहां पारंपरिक खाना परोसा गया। कुछ घंटों बाद, मेहमानों ने डायरिया, उल्टी, पेट दर्द और बुखार की शिकायत की। हालत बिगड़ने पर परिवार वाले उन्हें पास के हॉस्पिटल ले गए। हेल्थ अधिकारियों को शक है कि यह खराब खाने या पानी की वजह से हुई फ़ूड पॉइज़निंग है। शुरुआती जांच में यही वजह लग रही है, लेकिन इसकी पुष्टि लैब में जांच के बाद ही होगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. दिलीप पटनायक ने कहा कि 15 से ज़्यादा मरीज़ों का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ज़्यादातर की हालत स्थिर है और वे कड़ी मेडिकल निगरानी में हैं। एक मेडिकल टीम बचे हुए खाने और पानी के सैंपल लेने के लिए शादी की जगह पर जाएगी। इनकी जांच की जाएगी ताकि खराब होने का सोर्स पता चल सके। अधिकारियों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से कम्युनिटी गैदरिंग में फ़ूड सेफ़्टी को लेकर चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों ने लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए सावधानी और समय पर मेडिकल मदद पर ज़ोर दिया।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में आगामी राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह-2026 के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता का आयोजन

राउरकेला ०६/०३ (संवाददाता): आगामी 55वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 के उपलक्ष्य में सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सुरक्षा प्रशिक्षण हॉल में 'टूल किट सेफ़्टी टॉक' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ करना तथा सुरक्षित कार्य-संस्कृति को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से 60 से अधिक कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने कार्यस्थल के विभिन्न खतरों, निवारक उपायों एवं सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं पर प्रभावशाली सुरक्षा विचार-वार्ता प्रस्तुत कीं। इसके माध्यम से उन्होंने सुरक्षित एवं दुर्घटनारहित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के प्रति सराहनीय ज्ञान, स्पष्टता एवं प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। महाप्रबंधक (एसएंडएस-2) श्री एस के नायक प्रतियोगिता के निर्णायक थे। उन्होंने प्रतिभागियों का मूल्यांकन विषय-वस्तु, प्रस्तुतीकरण, व्यावहारिक प्रासंगिकता एवं संप्रेषण कौशल के आधार पर किया। महाप्रबंधक (एसईडी), श्री अबकाश बेहेरा एवं सहायक महाप्रबंधक (एसईडी) श्री बी के पाढ़ी ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

एनएच-143 पर सड़क हादसे में एनआईटी राउरकेला के छात्र की मौत, सहपाठी जिंदगी और मौत से जूझ रहा

राउरकेला ०६/०३ (संवाददाता): सुंदरगढ़ जिले में लहुनीपाड़ा पुलिस की सीमा के तहत राजामुंडा के पास नेशनल हाईवे 143 पर समर दरी चौराहे के पास एक डंपर ट्रक और उनके स्कूटर के बीच आमने-सामने टक्कर होने से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला के दूसरे साल के एक स्टूडेंट की मौत हो गई और एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। मरने वाले की पहचान कार्तिकेयन सेंथिल कृष्णन के रूप में हुई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का दूसरे साल का स्टूडेंट था। घायल स्टूडेंट, बसंती कार्तिक नारायण (19) का राउरकेला में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, 16 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप ङ्क 10 लड़के और 6 लड़कियां ङ्क सुंदर खंडाधार वॉटरफॉल देखने के लिए आठ किराए के स्कूटर पर निकले थे।

जब वे ह॥-143 पर समर दरी चौराहे से गुज़र रहे थे, तो राजामुंडा की तरफ से आ रहे एक डंपर ट्रक की सामने से आ रहे एक स्कूटर से आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर लगने से स्कूटर चला रहे कार्तिकेयन और पीछे बैठी बसंती मौके पर ही बुरी तरह घायल हो गए। साथी छात्रों ने तुरंत पुलिस को खबर दी, जिसके बाद लहुनीपाड़ा पुलिस स्टेशन की एक टीम एक्सीडेंट की जगह पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से लहुनीपाड़ा मेडिकल पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टरों ने कार्तिकेयन को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती इलाज के बाद, बसंती को एडवांस केयर के लिए राउरकेला के एक मेडिकल सेंटर में ले जाया गया। पुलिस ने मौके से डंपर ट्रक और खराब स्कूटर को कब्जे में ले लिया है। एक्सीडेंट किन हालातों में हुआ, यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।